(c) whether Government propose to make comprehensive modifications in the draft plan document; and

(d) if so, the steps since initiated in this direction?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) to (d). The new Government which has only recently assumed office proposes to consider the Plan afresh.

जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

115. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ढाई वर्षों में जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी उपयोग की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमण और द्वीव में विशेष जनजाति उपयोजनाएं बनाई गई हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की वे सभी प्रशासनिक एकाईयां (अर्थात ब्लाक, ताल्लुक) सम्मिलित हैं जिनमें 50 प्रतिशत और इससे अधिक आबादी जनजातियों की है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र 180 समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में गठित किये गये हैं और क्षेत्र की क्षमता और लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अलग विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी विकास क्षेत्र जैसे कृषि, जंगलात, पशुपालन, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित है। जनजाति उप-योजना का वित्तीय प्रबन्ध राज्य योजना विशेष केन्द्रीय संस्थागत वित्त और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधि से किया जाता है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए निधि का आवंटन और प्रयोग निम्न प्रकार से था:-

1977-78

	करोड़ रु०
राज्य योजनाओं से आवंटन	257.00
उपयोग किया गया	249.96
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	55.00
उपयोग किया गया	54.98

1978-79

राज्य योजनाओं से आवंटन	344.00
उपयोग किया गया	311.11
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	70.00
उपयोग किया गया (आंकड़े अधूरे है)	45.54

1979-80

राज्य योजनाओं से आवंटन	394.00
विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन	70.00

उद्योगों को वित्तीय सहायता

116. **श्री कृष्ण दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने देश में किन उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या उसका ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या किन्हीं उद्योगों ने सहायता राशि का दुरुपयोग किया है और यदि हां तो उन उद्योगों के नाम क्या है और वह राशि कितनी है ?

वित्त तथा उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन): (क) से (ग) निश्चित विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं है इस प्रकरण में जानकारी इकट्ठी करने में जो प्रयास किए जायेंगे उनके प्राप्त परिणाम तदनुरूपी नहीं होंगे।